1	2	3
22. Tamil Nadu	3727.9	1955.0
23. Tripura	184.0	50.2
24. Uttar Pradesh	2516.5	2028.5
25. West Bengal	4828.2	2656.9
Union Territories		
26. Andaman & Nicobar Islnands	17.2	8.6
27. Chandigarh	162.4	88.2
28. Dadra & Nagar Haveli	3.1	1.2
29. Delhi	910.8	663.7
30. Daman & Diu	2.7	1.3
31. Lakshadweep	6.9	1.7
32. Pondicherry	129.8	70.4
TOTAL	36305.7	21627.1

NOTE : *No Employment Exchange is functioning in this State.

कोयला का आयात

*197. **श्री गोपाल सिंह जी० सोलंकी** : क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने हाल ही में कोयले का आयात किया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मात्रा तथा मूल्य क्या है और उसका आयात किन-किन देशों से किया गया;

(ग) कोयले का आयात करने के क्या कारण हैं; और

(घ) देश में अच्छे किस्म के कोयले के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए क्या प्रयास किये गये हैं ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) से (ग) देश में न तो भारत सरकार और न ही कोयला मंत्रालय के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम उपभोक्ताओं को कोयले की आपूर्ति किए जाने के लिए कोयले का आयात कर रहे हैं । किंतु, एकीकृत इस्पात संयंत्र मुख्यतः निम्न राख वाले कोकिंग कोयले का आयात कर रहे हैं जो कि देशीय उपलब्धता तथा मांग के बीच के अंतराल को पूरा किए जाने और इस्पात संयंत्रों में प्रयोग के लिए समग्र रूप में मिश्रित करने के लिए कोयले की गुणवत्ता में सुधार किए जाने के लिए उसका आयात कर रहे हैं ।

पिछले 2 वर्षों में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अर्थात् भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि० (सेल) और विशाखा-पत्तनम इस्पात संयंत्र (वी० एस०पी०) आयात किए गए कोयले की कीमत और मात्रा के संबंध में ब्यौरा नीचे दिया गया है :

वर्ष	आयात (मि०टन में)	मूल्य (करोड़ रु० में)
1	2	3
1991-92		
सैल	4.255	672.50
वी०एस०पी०	0.990	186.03
जोड़	5.245	858.53

	आयात (मि० टन में)	मूल्य (करोड रु० में)
1992-93		
सैल	4.248	790.00
वी०एस०पी०	1.660	355.93
जोड़	5.908	1145.94

ये कोयला आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैण्ड और हालैण्ड से आयात किया गया था ।

(घ) लौह एवं इस्पात उद्योगों के प्रयोग के लिए कोकिंग कोयले की देशीय उपलब्धता में वृद्धि किए जाने के लिए, अन्य कदमों के अलावा, उठाये गये कुछ कदमों में निम्नलिखित कदम शामिल हैं :–

(1) विद्यमान वाशरियों का विद्यमान खानों का पुनर्गठन करके तथा नई खानों को विकसित करके कच्चे कोकिंग कोयले की आपूर्ति में वृद्धि किया जाना;

(2) निम्न ज्वलनशील कोकिंग कोयले के स्रोतों को सुदृढ़िकरण करके वाशरियों के फीड में वृद्धि किया जाना जिन्हे गुणवत्ता के आधार पर वर्ष 1984-85 में वाशरियों से असंयोजित कर दिया गया था और जिन्हें परीक्षण के बाद अब स्वीकार्य पाया गया है ;

(3) दो नई वाशरियों एक मधुबंद तथा एक केडला में विद्यमानधुलाई क्षमता में वृद्धि किए जाने के लिए चालू किए जाने की कार्रवाई को तेज किया जाना ।

(4) तकनीकी समिति की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए विद्यमान कोकिंग कोयले में सुधार किया जाना ताकि क्षमता उपयोगिता तथा धुले हुए कोककर कोयले की गुणवत्ता में सुधार किया जा सके ।

(5) इस्पात संयंत्रों में असम तथा मेघालय में उपलब्ध निम्न राख वाले कोककर कोयले का अधिक मात्रा में परिवहन किया जाना ।

Implementation of Barhawat Wage Board Recommendations

*198. SHRI RAMDAS AGARWAL: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) what efforts have so far been made by the Central Government for securing more extensive implementation of Bachawat Wage Board recommendations, and as on 28th July, 1993. how many establishments out of 1569 newspaper establishments have "ully/partly implemented them;

(b) what were the recommendations made in the last meeting of empowered committee in this regard; and

(c) what are the names of the states and Union Territories where neither Tripartite committees nor implementation cells have been formed so far and the details of the number of establishments which have challenged this Bachawat Wage Board Award and cases pending in the courts?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI P. A. SANGMA): (a) to (c) The onus for the implementation of the Bachawat Wage Board recommendations lies with the State Governments. The Central Government had requested the State Governments to ensure effective implementation of the recommendations of the Bachawat Wage Board. The State Governments were also requested to constitute "special cells" to oversee the implementation of these recommendations.

According to the latest information received from the State Governments and Union Territory administrations, out of 1557 newspaper establishments, 611 have fully implemented the recommendations of Bachawat Wage Board and 34 partly. The decisions taken by the Empowered Committee related to the matters concerning with Safety, Health & Hygiene, Over-